Representation of Employees' Association in Kendriya Vidyalaya Sangathan

2604. PROF. SAURIN BHATTACHARYA:

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether AIKVTA have demanded an immediate review of the nominations of employees associations' representatives of Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have undertaken the review; and

(d) if so, the details of the changes to be effected?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The General Secretary of All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association has suggested that:—

(i) the nominations should have been asked for from the respective associations;

(ii) representation should be on proportionate numerical strength of four categories of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan;

(iii) AIKVTA should be given three or more seats on Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors and the representation of one seat each to both factions of Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh should be annulled as RKVAS has still to prove 15 per cent of total teaching staff as their members;

(iv) nominations should be made by designation rather than by name.

(c) and (d) No, Sir. The Government decision was intended to give sufficient broad-based representation to the employees. It was not considered desirable to delay the matter further for the sake of agreement among all the associations. It is for the Government to make nominations of such persons whom it considers may contribute to the objectives of the Sangathan.

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संबंधी समझौते

2605. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संबंधी समझौतों का सदस्य है और यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि समझौते के अधिकांश सदस्य देशों में प्रतिलिप्याधिकार के प्रयोजन के लिए निर्धारित अवधि लेखक की मृत्यु के पश्चात पचास वर्ष की है जबकि भारत ने इस अवधि में दस वर्ष की वृद्धि कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट समझौतों अर्थात् साहित्यिक तथा कलात्मक कृति की सुरक्षा के लिए बर्न समझौता और विश्व जनीन कापीराइट समझौता, दोनों का एक सदस्य है । इन समझौतों में अपने सदस्य के लिए कापीराइट सुरक्षा के न्यूनतम स्तर स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक देश में अन्य सदस्य देशों में मूल रूप से तैयार होने वाली कृतियों की सुरक्षा प्रदान की गई है। दोनों समझौते एक-दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं ।

(ख) और (ग) इन समझौतों में न्यूनतम अवधि सहित कापीराइट सुरक्षा

न्यूनतम स्तर निर्धारित किए गए हैं । बर्न समझौते के अन्तर्गत अधिकांश मामलों में लेखक की मृत्यु के बाद वाले वर्ष से शुरु होने वाले 50 कैलेण्डर वर्ष न्यूनतम अवधि है, मामलों में कृति तैयार करने की तारीख से ऐसे 50 वर्ष और कुछ मामलों में ऐसे 25 वर्ष न्यूनतम अवधि है । विश्वजनीत कापीराईट समझौते के अन्तर्गत न्यूनतम अवधि और कम है । तथापि दोनो समझौतों के अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों को और अधिक अवधियां प्रदान करने की स्वतंत्रता है । भारत में, उन कृतियों के लिए, जो पहले से सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, कापीराईट (संशोधन) अध्यादेश 1991 द्वारा कुछ मामलों में लेखक की मृत्यु के बाद 50 कैलेण्डर वर्ष और अन्यों में प्रकाशन की तारीख के बाद ऐसे 50 वर्ष की पूर्व अवधि को और 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

कुछ अन्य विकासशील देशों सहित कुछ अन्य देशों में भी और अधिक अवधियां हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. कोटे डी आईवायरे	(99 वर्ष)
2. कोलम्बिया	(80 वर्ष)
3. गुयेना	(80 वर्ष)
4. पनामा	(80 वर्ष)
5. आस्ट्रिया	(70 वर्ष)
6. जर्मनी	(70 वर्ष)
7. इजराईल	(70 वर्ष)
8. ब्राजील	(60 वर्ष)
9. स्पेन	(60 वर्ष)

Special dispensation of Chairman, Kendriya Vidyalayas Sangathan

2606. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI MISA R. GANESAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 8000 children, mostly ineligible have been ordered admission in Kendriya Vidyalayas during the current academic session under the "Provision" of Special Dispensation of the Chairman;

(b) if so, what are the details of the Authority/Offlcers who made/ approved the relevant provision;

(c) what were the recommendations of Chandulal Chandrakar Committee in this regard;

(d) whether the recommendations have been shelved/rejected; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) In the current academic session 7052 admissions have been allowed on special dispensation of the Chairman.

(b) to (e) The Board of Governors on 31-5-1988 decided that a Sub-Committee may be constituted and the Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan may take a decision in the light of the report of the Sub-Committee. The Sangathan received the orders of the Chairman dated 3-8-1988 that special dispensation admission should be possible in the larger social considedation. The decision to have special dispensation admissions has been approved by succeeding Chairman also.

Staff Side Secretariat for Kendriya Vidyalaya

2607. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVATY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that AIKVTA have demanded establishment of a staff side Secretariat/Office under JCM Scheme for Kendriya Vidyalaya Sangathan;